कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख). "खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन और विपणन पुनर्व्यवस्था" नामक परियोजना के तहत, जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, छः राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में राज्य स्तर के तिलहन उत्पादक सहकारी संघ गठित किए जाने हैं। अब तक इस प्रकार के राज्य स्तर के संघ पांच राज्यों अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में राज्य स्तर का संघ अभी स्थापित किया जाना है।

National calamities Funds

39. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have considered the desirability of setting up National Calamities Fund, so that disasters like recent floods in Orissa can be attended to quickly and at the State level without involving the Centre for the release of funds which normally takes place after some time; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) The 7th Finance Commission examined the proposal regarding setting up a National Calamity Fund but did not consider it feasible to set up such a Fund. The Government of India accepted its recommendation.

(b) Does not arise.

खाद्यान्नों और दालों का उत्पादन

40. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अनुमानों के अनुसार इस वर्ष अनाज का कितना उत्पादन होने की आशा है ; और

(ख) खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्यों से 1982-83 के लिए खाद्यान्नों, दलहनों, मक्का आदि के उत्पादन के अनुमान अभी तक नहीं हुये हैं। तथापि इस वर्ष देरी से आए और कमजोर मानसून के कारण खरीफ उत्पादन के गत वर्ष की तुलना में कुछ कम होने की सम्भावना है।

(ख) सरकार ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और सूखे की स्थिति से पैदा होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सिंचाई जल की नियोजित निर्मुक्ति और अच्छे प्रबन्ध और फसल की उचित योजना तथा उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत को बढ़ा कर सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना।

(2) सूखे की स्थिति में कम संवेदनशील फसलों की उगाकार वैकल्पिक सस्य नीतियां अपनाना।

(3) सिंचाई पम्पसेटों के लिए डीजल और बिजली उपलब्ध कराना और नलकूपों आदि की मरम्मत करना।